



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082021-228685  
CG-DL-E-02082021-228685

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2021/श्रावण 11, 1943

No. 216]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2021/SHRAVANA 11, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

मामला सं. ए डी (ओआई) 11/2021

**विषय:** चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “(4आर-सीआईएस)-1, 1- डीमिथाइलइथाइल- 6 - स्यानोमिथाइल-2,2- डिमिथाइल -1, 3 - डायोक्सेन - 4 - एसीटेट जिसे एटीएस-8” के रूप में भी जाना जाता है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 6/11/2021-डीजीटीआर.—**

1. मै. आर्क फार्मा लैब्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे “याचिकाकर्ता” अथवा “आवेदक” भी कहा गया है), ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “(4आर-सीआईएस)-1, 1- डीमिथाइलइथाइल- 6 - स्यानोमिथाइल-2, 2- डिमिथाइल -1, 3 - डायोक्सेन - 4 - एसीटेट जिसे एटीएस-8” के रूप में भी जाना जाता है, (जिसे यहां आगे संबद्ध वस्तु अथवा विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

### **विचाराधीन उत्पाद**

3. विचाराधीन उत्पाद “(पीयूसी)” “(4आर-सीआईएस)-1, 1- डीमिथाइलइथाइल- 6 - स्यानोमिथाइल-2,2- डिमिथाइल -1, 3 – डायोक्सेन – 4 – एसीटेट जिसे एटीएस-8” के रूप में भी जाना जाता है। यद्यपि उत्पाद का रासायनिक नाम “(4आर-सीआईएस) – 1, 1- डीमिथाइलइथाइल – 6 -स्यानोमिथाइल -2, 2- डिमिथाइल -1, 3 – डायोक्सेन – 4 – एसीटेट” है। तथापि, इस उत्पाद को व्यापारिक नामों जैसे एटीएस-8, एएससी-3 पी, टी बी आई एन, स्यानो केटल यौगिक तथा एटोरवेस्टेटीन इंटरमीडिएट के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें से एटीएस-8 सबसे ज्यादा प्रचलित व्यापार नाम है।
4. ए टी एस – 8 एटोरवेस्टेटीन एपीआई (सक्रिय भेषज अवयव) के विनिर्माण के लिए प्रमुख मध्यवर्ती वस्तु है। एटोरवेस्टेटीन औषध सूत्र मनुष्यों में अधिक केलोस्ट्रोल की स्थिति को कम करने के लिए उपचार हेतु व्यापक रूप से प्रयोग होता है जो अन्यथा यदि उपचारित न हो तो कार्डियोवस्कुलर समस्याओं को जन्म दे सकती है जैसे हृदयघात और स्ट्रोक। यह एक जीवनरक्षक औषधि है जिसे अनिवार्य दवाइयों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह मध्यवर्ती वस्तु कंपनी द्वारा बल्क पावडर के रूप में विनिर्मित होती है और इसका कोई अलग ग्रेड या प्रचार नहीं है।
5. पीयूसी के आयातों की जानकारी आयातों के समय शुल्क के प्रयोजनार्थ अध्याय 29 के उपशीर्षों के अंतर्गत दी गई है जिनमें से सर्वाधिक आयात उपशीर्ष संख्या 2932 तथा 2933 के अंतर्गत हुए हैं। यद्यपि, अन्य उपशीर्षों जैसे 2915, 2916, 2917, 2918, 2926, 2931 तथा 2934 के अंतर्गत आयात भी याचिका के अनुसार हुए हैं।

### **ख. समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
7. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक और संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई प्रमुख अंतर नहीं है। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के “समान वस्तु” मानते हैं।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

8. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में **मै. आर्क फार्मा लैब्स लिमिटेड** द्वारा दायर किया गया है।
9. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

### **संबद्ध देश**

10. यह याचिका चीन जन.गण. से संबंधित उत्पाद के पाटन के संबंध में दायर की गई है। आवेदन के अनुसार एटीएस-8 केवल भारत और चीन जन.गण. में उत्पादित होता है।

### **कथित पाटन का आधार**

#### **क. सामान्य मूल्य**

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। आवेदक ने दावा किया है कि

विचाराधीन उत्पाद को अनेक एच एस कोडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इसलिए आवेदक के पास बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश ने लागत या कीमत या सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी उचित तीसरे देश से संबद्ध वस्तु से संबंधित कोई सटीक सूचना नहीं है। अतः संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान विधिवत रूप से समायोजित करके भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए लगाया गया है।

#### ख. निर्यात कीमत

12. आवेदक ने कतिपय समायोजना के पश्चात डी जी सी आईएंड एस के आयात आंकड़ों से प्राप्त सीआईएफ आयात कीमत से कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात की है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, डी/ओ प्रभार, संभलाई और निकासी प्रभार, के लिए समायोजनों का दावा किया गया है।

#### पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की तुलना की गई है जो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित सिद्ध करता है।

#### क्षति एवं कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

14. घरेलू उद्योग की क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण भारी कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री, कम क्षमता उपयोग और उद्योग को निरंतर घाटा हुआ है। इसके अलावा, खपत की प्रवृत्ति, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रौद्योगिकी और अन्य देशों से आयात में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
15. पूर्वोक्त से प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य पाते हैं जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### पाटनरोधी जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबंध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

#### जांच की अवधि (पीओआई)

17. प्रस्तावित पीओआई 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 महीने) की है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि में 2017- 18, 2018- 2019, 2019- 20 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

#### सूचना प्रस्तुत करना

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dir11-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के

माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उक्त पैरा 18 में उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

#### **ठ. समय-सीमा**

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in), [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in), [dir11-dgtr@gov.in](mailto:dir11-dgtr@gov.in), [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भी प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

#### **अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि,

आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

33. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

### **असहयोग**

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2021

(Case No. AD-OI-11/2021)

**Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8” originating in or exported from China PR.**

**No- 6/11/2021-DGTR.—**

1. An application has been filed by **M/s. Arch Pharma labs Limited** (hereinafter referred to as the ‘the petitioner’ or ‘the applicant’) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as ‘the Authority’) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of an anti-dumping duty concerning imports of “**(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8**” (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. The applicant has alleged that the domestic injury is suffering material injury due to the dumped imports of subject goods from the subject country, and has requested for imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country.

**Product under consideration**

3. The product under consideration (“PUC”) is “(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate also known as ATS-8”. While the chemical name of the product remains “(4R-Cis)-1,1-Dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate” the product is also known in trade names like ATS-8, ASC-3P, TBIN, Cyano Ketal Compound and Atorvastatin Intermediate wherein ATS-8 is the most commonly used trade name.
4. ATS-8 is a key intermediate for manufacture of Atorvastatin API (Active Pharmaceutical Ingredient). Atorvastatin drug formulation is widely used to treat for lowering of excess cholesterol condition in the human beings, which can otherwise lead to cardio vascular problems like heart attack and stroke, if not treated. This is a lifesaving drug finding classification under the National List of Essential Medicines (NLEM). The intermediate is manufactured in the form of bulk powder by the company and does not have any separate grades or types.
5. The imports of the PUC have been reported under subheadings of Chapter 29 for the purpose charging of duty at the time of imports with highest imports having been reported under subheading numbers 2932 and 2933 though there have been imports under other subheadings like 2915, 2916, 2917, 2918, 2926, 2931 and 2934 also as per the petition.

**Like Article**

6. The applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.
7. The applicant has claimed that there are no known major differences in the production process employed by the applicant and the exporters from the subject countries. Therefore, for the purposes of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as “like article” to the product under consideration being imported from the subject country.

**Domestic Industry and Standing**

8. The application has been filed by **M/s. Arch Pharma labs Limited** as the domestic industry.
9. The applicant has submitted that they are the sole producer of the subject goods in India. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti-dumping Rules.

**Subject Country**

10. The petition has been filed in respect of the dumping of the product concerned from China PR. As per the application, ATS-8 is only produced in India and in China PR.

**Basis of alleged dumping**

**a) Normal Value**

11. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para-7 of Annexure-I to the Rules. The applicant has claimed that the product under consideration is classified under multiple HS codes and therefore the applicant does not have accurate information regarding the cost or price in a market economy third country, or the export price of the subject goods from an appropriate third country for determination of the normal value. Therefore, the normal value for the subject country has been estimated by considering the normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

**b) Export Price**

12. The applicant has arrived at the export price at ex-factory level from the CIF import price obtained from DGCI&S import statistics after making certain adjustments. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, D/O charges, handling & clearing charges to arrive at the export price at the ex-factory level.

**Dumping Margin**

13. The normal value and the ex-factory export price have been compared which shows significant dumping above de minimis in respect of the subject goods from the subject country. There is sufficient prima facie evidence that subject goods are being exported to India at a price below the normal value, resulting in the dumping of the subject goods from the subject country, justifying initiation of an antidumping investigation.

**Evidence of Injury and Causal Link**

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding it being materially injured on account of dumping of the subject goods from subject country. It has claimed that there is significant price suppression, price underselling, low-capacity utilization and continued losses to the industry on account of the dumped imports. Further, there is no change in the pattern of consumption, trade restrictive practice, change in the technology and the imports from other countries which could have contributed to the injury being suffered by the domestic industry.
15. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, causing injury to the domestic industry and the causal link between the alleged dumping and injury sufficient to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Initiation of anti-dumping investigation**

16. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted, about the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Period of Investigation (POI)**

17. The proposed POI is from 1st April 2020 to 31st March 2021 (12 Months). The injury investigation period for the present investigation will be 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI.

**Submission of information**

18. In view of the special circumstances arising out of the COVID-I9 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adgl11-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in, dir11-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF / MS Word format and data files are in MS Excel format.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned in Para 18 above.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.



**Time-limit**

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email [adg11-dgtr@gov.in](mailto:adg11-dgtr@gov.in), [dir13-dgtr@gov.in](mailto:dir13-dgtr@gov.in), [dir11-dgtr@gov.in](mailto:dir11-dgtr@gov.in), [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in), within thirty days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of the explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limits.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

**Submission of information of non-Confidential basis**

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately:
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority.
32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.



**Inspection of Public File**

33. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

**Non-cooperation**

34. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority